चुराह विधानसभा क्षेत्र के जनजातीय गांवों को आदर्श मॉडल बनाने की तैयारी

आदि कर्मयोगी योजना के तहत 41 जनजातीय गांवों का होगा विकास

मंजूर पठान | चंबा
समर न्यूज़

चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए एक बड़ी पहल शुरू की जा रही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'आदि कर्मयोगी योजना' के तहत चुराह के 41 जनजातीय गांवों को समग्र रूप से विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

इन गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, सिंचाई एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं को बेहतर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य है कि दुर्गम क्षेत्रों के निवासियों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जाए।

इन दिनों विकास खंड तीसा में इस योजना के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। खंड विकास अधिकारी कार्यालय, तीसा की पहल पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों, पंचायत सचिवों और तकनीकी कर्मचारियों की संयुक्त टीम बनाई गई है। यह टीमें चिन्हित पंचायतों के गांवों का दौरा कर रही हैं, जहां वे जमीनी स्तर पर आवश्यकताओं

खंड विकास अधिकारी तीसा अरविंद कुमार

और कमियों का आकलन कर रही हैं। अभी तक विकास खंड की 53 पंचायतों में से कुल 41 ऐसे गांव चिन्हित किए गए हैं, जिनमें अनुसूचित जनजाति समुदाय की आबादी रहती है और जहां इस योजना के तहत समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों को तेज गति से विकास की मुख्यधारा में शामिल करना है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और पंचायत सचिवों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। प्रत्येक टीम अपने-अपने क्षेत्र के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर रही है, जिसमें स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ करना, पेयजल योजनाओं को बेहतर बनाना, स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सड़क सुविधा उपलब्ध कराना और आजीविका बढ़ाने वाले प्रयास शामिल किए जा रहे हैं।

अरविंद कुमार ने कहा कि तैयार की गई कार्ययोजना को जल्द ही उच्च अधिकारियों के समक्ष भेजा जाएगा, ताकि स्वीकृति मिलने के बाद विकास कार्यों पर तेजी से अमल शुरू किया जा सके। उन्होंने विश्वास जताया कि इस योजना के क्रियान्वयन से चुराह के जनजातीय गांवों का समग्र विकास होगा और लोगों को बुनियादी सुविधाएं उनके ही गांवों में उपलब्ध हो सकेंगी।

नूरपुर पुलिस का नशे के खिलाफ बड़ा अभियान, हेरोइन और नकदी बरामद

संजीव | नूरपुर
समर न्यूज़

जिला नूरपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कई तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन कार्रवाइयों में पुलिस टीमों ने हैरोइन और नकदी सहित महत्वपूर्ण सामग्री बरामद की है।

पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पहली कार्रवाई पुलिस थाना डमटाल के अंतर्गत गांव छत्री में की गई। यहां पुलिस ने आरोपी महिंदरपाल को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 11.22 ग्राम हैरोइन और 22,000 रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस ने मौके पर ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरे मामले में पुलिस थाना

पुलिस हिरासत में आरोपी। -समर न्यूज़

नूरपुर की टीम ने अभियोग संख्या 235/25 के तहत नूरपुर किला क्षेत्र में कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने दो आरोपियों हर्ष पुत्र अजय और कर्म चंद पुत्र छोटू राम—को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 6.56 ग्राम हैरोइन बरामद की गई।

एसपी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि जिला नूरपुर में नशे के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी है और आने वाले समय में इसे और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने में स्थानीय लोग सहयोग करें। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की भी अपील की।

सैकड़ों लोगों की मौत और तीन साल की नाकामी के बाद किस बात का जश्न मनाएगी सरकार : जयराम ठाकुर

समर न्यूज़ | शिमला

विधान सभा कार्यालय शिमला में मीडिया के प्रतिनिधियों से बात करते हुए नेता पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा की वजह से प्रदेश में लगभग पांच सौ लोगों की जान गई है और हजारों लोग बेघर हुए हैं। हजारों बीघा फसल और हजारों पशुओं की मौत भी इस आपदा की वजह से हुई है। हर पीड़ित तक सरकार अभी राहत नहीं पहुंचा पाई है। इसके अलावा सुख की सरकार के 3 साल का कार्यकाल भी नाकामी और निराशा से भरा रहा है। इसके बाद भी सरकार अपने तीन साल के पूरे होने का जश्न मनाने जा रही है। इसी के साथ कांग्रेस के नेताओं द्वारा कहा

जयराम ठाकुर बातचीत करते हुए। -समर न्यूज़

जा रहा है कि इस जश्न में दिल्ली से भी बड़े नेता आ सकते हैं। यदि कांग्रेस के नेताओं में जरा सी भी लज्जा बची है तो उन्हें इस कार्यक्रम को रद्द करके आपदा प्रभावितों को सही मायने में राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल की आपदा में हर बार केंद्र का अद्वितीय सहयोग रहा है। 2023 की आपदा में सेना के हेलीकॉप्टर से आपदा स्थल तक जेसीबी मशीन पहुंचाई गयी। आपदा प्रभावितों तक राशन पहुंचाने से लेकर उन्हें रेस्क्यू करने तक सेना, एनडीआरएफ, सेंट्रल फोर्सेज, वायु सेना की अहम भूमिका रही। 2023 से अब तक आपदा रात के नाम पर 5500 करोड रुपए से ज्यादा की धनराशि दी गई है। इसके अलावे एनडीआरएफ और एनडीएमएफ के तहत लगभग 225 करोड़ केंद्र द्वारा इस वर्ष हिमाचल को एडवांस में दिए गए हैं। इसके बाद भी आपदा प्रभावितों को सरकार 400 करोड रुपए की धनराशि भी नहीं दे पाई है। जबकि सुक्खू सरकार ने स्पेशल पैकेज 4500 करोड़ रुपए का घोषित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए देने की बात कही है तो वह पत्थर की लकीर है। उस घोषणा की एक-एक पाई हिमाचल प्रदेश को मिलेगी। हिमाचल में पहली बार आपदा का दौरा करने प्रधानमंत्री आए।

नरेंद्र मोदी की गारंटी पर पूरा देश भरोसा करता है। मुख्यमंत्री केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए आपदा राहत के 5500 करोड रुपए का हिसाब भी तो दें? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस को अपनी हार का अंदाजा पहले से ही था इसलिए उन्होंने वोट चोरी का माहौल बनाने का प्रयास किया। कांग्रेस के नेता एनडीए सरकार की एंटी इनकंबेंसी के भरोसे जीतना चाहते थे लेकिन वह भूल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति में प्रो इनकंबेंसी का नया दौर शुरू किया है।

पधर में निर्माण होगा इनडोर स्टेडियम, भूमि अधिग्रहण को मंजूरी

केंद्र से फंडिंग का इंतज़ार, प्रदेश सरकार लगभग 1 करोड़ 45 लाख रुपये खर्च करेगी

धर्मवीर | मंडी
समर न्यूज़

मंडी जिले में खेलो इंडिया परियोजना के तहत प्रस्तावित इनडोर स्टेडियम अब रघुनाथ का पधर में बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने यहां 12 बीघा निजी भूमि को अधिग्रहित करने की औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी है।

इस भूमि के अधिग्रहण पर सरकार लगभग 1 करोड़ 45 लाख रुपये खर्च करेगी। मंडी सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिग्रहण से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और फाइल अब खेल विभाग

भाजपा विधायक अनिल शर्मा जानकारी देते हुए। -समर न्यूज़

के अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। जैसे ही वित्त विभाग को भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव प्राप्त होगा, धनराशि जारी होने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

अनिल शर्मा के अनुसार, पहले इनडोर स्टेडियम को पड्डल मैदान में बनाने की योजना इसलिए तैयार की गई थी क्योंकि उस समय वहां भूमि उपलब्ध थी और इसी आधार पर डीपीआर भी तैयार की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी मंशा कभी भी पड्डल में बड़ा ढांचा खड़ा करने की नहीं थी, बल्कि परियोजना की आवश्यकता के अनुसार डीपीआर तैयार की गई थी।

अब, रघुनाथ का पधर में भूमि उपलब्ध होने के बाद स्टेडियम का निर्माण वहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रघुनाथ का पधर में स्वास्थ्य विभाग का कब्जा निजी भूमि के एक हिस्से पर था, जिसे अब खेल विभाग द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है।

भूमि अधिग्रहण पूरा होते ही केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि उपलब्ध होने पर निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

अनिल शर्मा ने यह भी कहा कि इनडोर स्टेडियम के लिए केंद्र सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत 18 से 20 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करेगी।

हालांकि, परियोजना की डीपीआर की फाइल अभी भी प्रदेश सरकार के पास लंबित है। विधायक ने बताया कि इस फाइल को खेल सचिव तक पहुंचाने के लिए उन्हें काफी प्रयास करने पड़े। अब प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया है कि वह इस फाइल को जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भेजे, ताकि धनराशि समय पर स्वीकृत हो सके और निर्माण कार्य में देरी न हो।

हमीरपुर में स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट रफ्तार पर, अब तक 3 हजार मीटर बदले

स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट के संचालन के लिए अधीक्षण अभियंता कार्यालय के पास ही एक कंट्रोल रूम बनाया गया

अरविंद | हमीरपुर
समर न्यूज़

हमीरपुर जिला में बिजली उपभोक्ताओं को आधुनिक और पारदर्शी प्रणाली से जोड़ने के लिए स्मार्ट मीटर परियोजना तेज गति से आगे बढ़ रही है। जिले में प्रथम चरण के तहत अब तक तीन हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इन मीटरों को मुख्य रूप से सरकारी भवनों और कमर्शियल संगठनों में स्थापित किया गया है, जहां पुराने मीटरों को हटाकर अत्याधुनिक स्मार्ट मीटरों की सुविधा प्रदान की गई है।

हमीरपुर में स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट। -समर न्यूज़

बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता ई. आशीष कपूर ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने की इस प्रक्रिया से बिजली की खपत और बिलिंग प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी होगी। स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी पर पूर्ण विराम लगने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को उपभोग किए गए बिजली की सही जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध होगी। कुछ उच्च बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं को भी इस चरण में स्मार्ट मीटर से जोड़ दिया गया है। स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट के संचालन के लिए अधीक्षण अभियंता कार्यालय के पास ही एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहां से संबंधित कंपनी पूरे सिस्टम की निगरानी और संचालन करेगी। ट्रांसफार्मर स्तर पर लगाए गए इन स्मार्ट मीटरों से उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाली बिजली का पूरा रिकार्ड दर्ज होगा।

अधिकारियों के अनुसार, परियोजना का दूसरा चरण भी आवार्ड किया जा चुका है। इस चरण में जिले के एक लाख 72 हजार उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर सुविधा से जोड़ा जाएगा। आने वाले समय में पूरे हमीरपुर जिला में पारंपरिक मीटरों की जगह स्मार्ट मीटर ही लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर प्रणाली लागू होने के बाद बिजली बिलों के भुगतान में भी उपभोक्ताओं को सहूलियत मिलेगी। समय पर बिल जमा न कराने वाले उपभोक्ताओं की जानकारी स्वतः सिस्टम में दर्ज होगी, जिससे डिफॉल्टरों पर त्वरित कार्रवाई करना संभव होगा। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में स्मार्ट मीटर में और भी आधुनिक फीचर जोड़े जा सकते हैं।

हिमाचल सरकार ने मंत्रियों के यात्रा और दैनिक भत्ते बढ़ाए, नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू किए

समर न्यूज़ | शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्रियों को मिलने वाले यात्रा और दैनिक भत्तों से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार मंत्रियों के माइलेज भत्ते और दैनिक भत्ते दोनों में बढ़ोतरी की गई है। नए प्रावधानों के लागू होने के साथ ही यात्रा के दौरान होने वाले खर्चों के अनुरूप भुगतान व्यवस्था को अद्यतन किया गया है।

संशोधित नियमों के तहत अब मंत्रियों को पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में सड़क मार्ग से यात्रा करने पर माइलेज भत्ते

के रूप में 18 रुपये प्रति किलोमीटर के स्थान पर 25 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेंगे। सरकार का कहना है कि यह संशोधन मौजूदा यात्रा व्यय को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिससे वास्तविक लागत के अनुरूप भत्ता दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, मंत्रियों को यात्रा या आधिकारिक दौरे के दौरान मिलने वाले दैनिक भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें प्रति दिन 2500 रुपये का भत्ता दिया जाएगा, जबकि पहले यह राशि 1800 रुपये निर्धारित थी। इससे आधिकारिक यात्राओं के दौरान होने वाले खर्चों का समुचित वहन सुनिश्चित होगा।

हिमाचल प्रदेश मंत्रियों का यात्रा भत्ता नियम, 2000 में संशोधन किया है। यह संशोधन सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट, 2000 की धारा 14 और 15 के तहत किया गया है। सरकार का कहना है कि ये संशोधन प्रशासनिक जरूरतों और मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप किए गए हैं ताकि मंत्रियों को क्षेत्रीय परिस्थितियों के आधार पर उचित और यथार्थवादी भत्ता प्राप्त हो सके।

संजौली मस्जिद मामले पर हिंदू संगठनों का आमरण अनशन जारी

संजू | शिमला
समर न्यूज़

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद से जुड़े विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। प्रदर्शनकारी समूह ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो शुक्रवार को व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। हिंदू संगठनों से जुड़े नेताओं विजय शर्मा और मदन ठाकुर ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे झूठे हैं। इन्हें बिना देरी वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन उनकी मांग पर विचार नहीं करता, तो

संजौली थाना परिसर के बाहर आमरण अनशन पर बैठे लोग। -समर न्यूज़

प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा 11 सितंबर 2024 को हुए आंदोलन से भी व्यापक होगी। प्रदर्शनकारियों ने विवादित स्थल पर नियमों के अनुपालन की मांग उठाते हुए कहा है कि मस्जिद में अवैध निर्माण के बाद बिजली और पानी के कनेक्शन नियमों के अनुसार रोके जाएं और वहां की गतिविधियों को फिलहाल स्थगित किया जाए। देवभूमि संघर्ष समिति सहित अन्य संगठनों ने सरकार और जिला प्रशासन को 24 घंटे की समय-सीमा दी है।

तीन प्रमुख मांगों : दर्ज मुकदमों को वापस लेना, विवादित स्थल पर कार्यवाही और बिजली-पानी की सप्लाई पर निर्णय पर यदि स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया, तो शुक्रवार को संजौली में एक बार फिर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। संगठनों का कहना है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन प्रशासन यदि कार्रवाई में देरी करता है, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।

मंडी की उपेक्षा, कई संस्थान राज्य सरकार ने बंद किएः अजय

धर्मवीर। मंडी
समर न्यूज़

हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा 11 दिसंबर को मंडी में आयोजित किए जाने वाले तीन वर्ष पूरे होने के समारोह को लेकर भाजपा ने गंभीर सवाल उठाए हैं। अजय ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सरकार के पास तीन वर्षों की कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं है, जिसे जनता के सामने गौरवपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। ऐसे में सरकार अब बड़े मंचों और लंबे भाषणों के जरिए जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि मंडी जिला सरकार की उपेक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण रहा है, जहां कई संस्थान बंद किए गए, कई

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय ठाकुर मंडी में प्रेस से बातचीत करते हुए।-समर न्यूज़

को शिफ्ट किया गया और कई विकास कार्यों को ठप कर दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आपदा जैसी गंभीर परिस्थितियों में, जब मंडी और अन्य क्षेत्रों में लोगों को तत्काल राहत और सहयोग की जरूरत थी, तब सरकार चुनावी गतिविधियों में व्यस्त रही। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जनता मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली को भली-भांति समझ चुकी है और अब सरकार की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। अजय ठाकुर ने कहा कि वहां महाठगबंधन ने भी जनता को भरमाने का प्रयास किया। जनता ने विकास को प्राथमिकता देते हुए जनादेश दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि वहां उनके चुने गए विधायक एक आल्टो कार में बैठकर विधानसभा पहुंच सकते हैं। हिमाचल में भी कांग्रेस की हालत इससे भी खराब होने वाली है और आने वाले चुनावों में पार्टी विधायक टू-व्हीलर में यात्रा करने लायक संख्या में ही बचेंगे। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस को चाहिए कि वह जश्न मनाने के बजाय जनता से किए वायदों को पूरा करे और प्रदेश में विकास कार्यों को गति दे, क्योंकि जनता अब दिखावे से प्रभावित होने वाली नहीं है।

हिमाचल में 6297 स्कूलों में नर्सरी शिक्षक नहीं

जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं की नियुक्ति की मांग

समर न्यूज़ | शिमला

हिमाचल प्रदेश के हजारों स्कूलों में प्री-प्राइमरी स्तर पर शिक्षकों की भारी कमी के बीच, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री डॉ. मामराज पुंडीर ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को नर्सरी शिक्षक के रूप में अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 6297 सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति न होने से प्रारंभिक बाल शिक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। डॉ. पुंडीर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (JBT) का दो वर्ष

डॉ. मामराज पुंडीर

का गहन प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं, लेकिन लंबे समय से बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जब प्रदेश के हजारों स्कूल नर्सरी शिक्षकों से वंचित हैं, तो जेबीटी प्रशिक्षित युवाओं को नियुक्त करना न केवल शिक्षा के हित में होगा, बल्कि रोजगार की दिशा में भी बड़ी राहत प्रदान करेगा।उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हाल ही में सरकार को 10,000 से अधिक नियुक्ति आवेदन भेजे गए थे, लेकिन इनमें से 9986 आवेदनों को खारिज कर दिया गया, जो इस महत्वपूर्ण विषय के प्रति सरकारी संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है। डॉ. पुंडीर के अनुसार, यह स्थिति चिंताजनक है और सरकार को तुरंत सकारात्मक व ठोस कदम उठाने चाहिए।

डॉ. पुंडीर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हवाला देते हुए कहा कि प्रारंभिक बाल शिक्षा को मजबूत करना समय की आवश्यकता है। इसके लिए स्थानीय, प्रशिक्षित और योग्य जेबीटी पास युवाओं को नर्सरी शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए।

बदला मौसम शिमला और कसौली में रात का तापमान 10 डिग्री रहा, चार जगह माइनस में पहुंचा पारा

सुंदरनगर, बिलासपुर में छाया कोहरा, दिन में खिली धूप

समर न्यूज़ | शिमला

हिमाचल प्रदेश में मौसम के तेवर बदलने लगे हैं। राजधानी शिमला और पर्यटक स्थल कसौली में न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे इन दोनों क्षेत्रों में रविवार की रात का तापमान दस डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। पहाड़ी राज्य के अधिकांश हिस्सों में जहां रातें और ठंडी होती जा रही हैं, वहीं शिमला और कसौली में बढ़ती रात की गर्माहट मौसम में हल्का बदलाव दिखा रही है।

इसके विपरीत प्रदेश के अन्य कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान दस डिग्री से नीचे बना हुआ है, जिससे मैदानी

शिमला में मौसम के बदलते तेवर

इलाकों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक ठंडक में इजाफा महसूस किया जा रहा है।

सोमवार सुबह सुंदरनगर में घना कोहरा छाया रहा, जबकि बिलासपुर में सुबह और शाम दोनों समय हल्का कोहरा देखने को मिला। दिन के समय पूरे प्रदेश में धूप खिली रही, जिसने ठंड में थोड़ी राहत जरूर दी। मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल में 23 नवंबर तक मौसम साफ बने रहने की संभावना है और फिलहाल बारिश व बर्फबारी के कोई संकेत नहीं हैं। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है, जिससे रातें अधिक सर्द हो गई हैं। चार स्थानों पर पारा रविवार रात को शून्य से नीचे रिकॉर्ड किया गया। इनमें सबसे कम तापमान लाहौल-स्पीति के ताबो में माइनस 5.0 डिग्री सेल्सियस रहा। कुकुमसेरी में माइनस 4.9, केलांग में माइनस 1.0 और समदो में माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ।

अन्य प्रमुख स्थानों में शिमला का न्यूनतम तापमान 10.2, कसौली का 11.1, सुंदरनगर का 5.0, भुंतर का 3.9, कल्पा का 4.4, धर्मशाला का 8.6 और ऊना का 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा। सोलन में 4.0, मनाली में 3.7, मंडी में 6.8, बिलासपुर में 8.5, हमीरपुर में 6.5 और कुफरी में 9.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसी प्रकार नारकंडा में 7.1, भरमौर में 9.2 और सेऊबाग में 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।अधिकतम तापमान की बात करें तो सोमवार को ऊना सबसे गर्म रहा, जहां पारा 26.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। हमीरपुर में 25.4, नाहन में 25.0, सोलन में 24.0, कांगड़ा में 23.7, धर्मशाला में 22.0, शिमला में 20.2, मनाली में 19.2 और केलांग में 14.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।